[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

टेंडर मंगवाए जाते थे, लेकिन 1966-67 से उस ने टेंडर मंगवाने बन्द कर दिये और नेगोशिएशन्ज कर के ये शीशियां सप्लाई करने का कन्ट्रैक्ट जे० जी० ग्लास इंडस्ट्रीज को दे दिया। यह कम्पनी किस की है ? श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के दो लड़के उस के डायरेक्टर हैं। वे शीशियां 42 रुपये फ़ी-हज़ार के हिसाब से खरीदी जा रही हैं। हम पब्लिक सेक्टर को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन कई लोग उस को कमज़ोर करने के लिए साजिशें करते हैं। इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ़ से ये शीशियां 42 रुपये फ़ी-हज़ार के हिसाब से खरीदी जा रही हैं, जब कि बाज़ार में उन की प्राइस 30 रुपये फ़ी-हजार है। इस प्रकार 27 लाख रुपया सालाना फ़ालतू दिया जा रहा है। दो साल में 54 लाख रुपया ज्यादा अदा करने का यह स्कैंडल है। ये शीशियां सारे हिन्दुस्तान में बनती हैं, लेकिन इस के लिए टेंडर काल नहीं किया गया है, बल्कि यह कन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन्ज के आधार पर दिया गया है।

अब मैं इनकम टैक्स का एक केस आप के सामने रखना चाहता हूं। फ़िनांस मिनिस्टर साहब इस वक्त हाउस में नहीं हैं। मैं उन के नोटिस में यह मामला लाना चाहूंगा। श्री पी० आर० नायक ने एक नोट डामले साहब को भेजा, जो उस वक्त मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, कि वेक्टल्ज कम्पनी के इनकम टैक्स की जिम्मेदारी हम लेते हैं, जो कि करीब पांच सात लाख रुपये होगा। यह बात रिकार्ड पर, फाइल में है। डामले साहब इस बात को मान गए, क्योंकि इस कम्पनी को दो करोड़ रुपया मुआवज़ा देना था। लेकिन बाद में जो एसेसमेंट आया, उस के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख रुपये का इनकम टैक्स बनता है, जो कि इंडियन आयल कम्पनी को देना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर घाटे में क्यों न जाये, जब कि सेक्रेटरी और चेयरमैन इस तरह की बेईमानी करते हैं। उस की सारी कमाई इस 1,60 लाख रुपये में चली जायेगी।

अब मैं बीस करोड़ वाली बात बताता हूं। हल्दिया-बरौनी की पाइप-लाइन तैयार होने के बाद तीन साल तक बन्द रही। उस दौरान मुकदमेबाजी चलती रही और खर्चा पड़ता रहा। 10 परसेंट के हिसाब से तीन साल में मशीनरी का डैप्रिसियेशन 4,80,00,000 रुपया होता है। तीन साल तक हम तेल के ट्रांसपोर्ट पर बीस लाख रुपये हर मास फ़ालतू देते रहे, जो कि मिला कर 7,20,00,000 रुपया बनता है। 2,78,00,000 रुपया इन्ट्रेस्ट पड़ा है। उस के अलावा 1,12,00,000 रुपया एस्टाब्लिशमेंट वगैरह पर हुआ। ये सब मिला कर 16,42,00,000 रुपये हुए।

इस के साथ ही इनकम टैक्स : 1,50,00,000 रुपया पाइप-लाइन में नुक्स : 1,00,00,000 रुपया, इंडियन आयल कम्पनी : 40,00,000 रुपया, इंडियन रिफ़ाइनरीज़ लिमिटिड : 17,00,000 रुपया और हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स लिमिटिड : 54,00,000 रुपया भी मिला कर कुल 20,03,00,000 रुपये का यह अनुचित खर्चा है।

मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब एक एन्क्वायरी कमेटी बिठायें, जो इस बात की जांच करे कि पिछले कुछ सालों में इस डिपार्टमेंट में यह जो बीस करोड़ रुपये का स्कैंडल हुआ है, उस के लिए कौन जिम्मेदार है।

इन सब बातों के बावजूद भी मैं समझता हूं कि इस मिनिस्ट्री की मांगें मन्ज़ूर की जानी चाहिए और मैं उन का समर्थन करता हूं।

16.28 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Twenty eight Report

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठाइसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में 17 अप्रैल, 1968 को पेश किया था, सहमत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House agrees with the Twenty-eight Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 17th April, 1968".

The motion was adopted

— — —

16. 28½ hrs.

RESOLUTION RE : REORGANISATION OF PLANNING COMMISSION—*Contd*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up further discussion of the following Resolution moved by Shri S. Xavier on the 5th April, 1968 :—

"This House is of opinion that the Planning Commission be reorganised on the basis of the recommendations of the Administrative Reforms Commission".

One hour and thirty minutes have been allotted for this. The hon. Member has taken one minute. He should finish in 15 minutes.

SHRI SHRI CHAND GOEL (Chandigarh) : The time is not sufficient. It should be extended.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : It had got to be extended.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is a serious question which is being debated. We shall see. Another Resolution is also there. He must get his time.

Mr. Xavier, to continue his speech.

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli) . Mr. Deputy-Speaker, Sir, the text of my resolution reads as follows :

"This House is of the opinion that the Planning Commission be reorganised on the basis of the recommendations of the Administrative Reforms Commission".

At the outset, I would submit that this is a very serious subject, and the fate and the lot of the people of the country are dependent upon the plans that have been formulated or that are to be formulated in the Fourth Plan.

Hitherto, the Planning Commission has been working on some basis, and has given many plans, especially the three Five Year Plans. Now, Government have set up the Administrative Reforms Commission to go into the administrative set-up of all the spheres of Government so that the efficiency and economy of the entire administrative set-up can be assesed by the commission and economy and efficiency could be brought about or maintained on the lines indicated by the commission. So, the importance of the Administrative Reforms Commission cannot be underrated. If certain reforms have to be effected, then the recommendations of the Admisnitrative Reforms Commission have to be adhered to, and have to be respected. If the recommendations of the Administrative Reforms Commission are thrown out or are rejected, then it means that we have no respect for the Administrative Reforms Commission and its recommendations.

If that be the mentality or the attitude of Government, then there is no necessity to have set up the Administrative Reforms Commission at all. I was surprised to see in yesterdays' papers that a full meeting of the Planning Commission held in Delhi under the chairmanship of the Prime Minister rejected the Administrative Reforms Commission's suggestion for change in the original terms of reference of the planning body to give it the expert character. If that be their attitude to the recommendations of the Administrative Reforms Commission in respect of the Planning Commission and that too under the chairmanship of the Prime Minister. then where is the necessity for this Administrative Reforms Commission at all? Why should the Administrative Reforms Commission continue to work at all ? So, I would say straightway that the Administrative Reforms Commission has been slighted under the chairmanship of the Prime Minister herself.

I would submit that this sort of attitude towards the Administrative Reforms Commission must cease. Otherwise, we could as well scrap the Administrative Reforms Commission itself by now.

Now, I would come to the recommendations of the Administrative Reforms Commission in brief.